

# 'पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार दिया, हम सपने पूरे कर रहे हैं'

## मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर में नियुक्ति पत्र, ट्राई साइकिल, स्कूटी, कृत्रिम अंग व आयुष्मान कार्ड बांटे

जोधपुर, 12 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार दिया, हम सपने पूरे कर रहे हैं। सी.एम. ने युवाओं से कहा, आपने जो सपने सजोए हैं, हमारी सरकार उन्हें पूरा करेगी। इस दौरान आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में उन्होंने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे, साथ ही रिमोट से कई योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रोजगार उत्सव में करीब पांच हजार लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, ट्राई साइकिल, स्कूटी, कृत्रिम अंग व आयुष्मान कार्ड वितरित किए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैसलमेर, चूरू, दौसा से नर्सिंग ऑफिसर, संगणक आदि पद पर नव निर्वाचित लोगों से बात कर, बधाई दी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की है, भारत के युवाओं की है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। प्रधानमंत्री ने यह करके दिखाया है।

कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर ने अपने उद्बोधन में कहा, यह तो अभी ट्रेलर है, अभी 10 हजार नियुक्तियां हो गई हैं, मार्च अप्रैल तक 50 हजार नियुक्तियां होंगी।

कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर, शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, विधायक अतुल भंसाली, देवेन्द्र जोशी, पम्बराम विश्वास, अर्जुनलाल गर्ग सहित कई जनप्रतिनिधि

## सिंधिया से माफी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर किसी को भी किसी अन्य पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

बुधवार को जब बनर्जी आपदा प्रबंधन अधिनियम के संशोधन पर चल रही चर्चा में भाग ले रहे थे तब तृणमूल कोविड-19 के दौरान केन्द्र सरकार पर असहयोग आरोप लगाया। जिसका भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने विरोध किया।

उन्होंने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोविड वैकसीन के परिवहन में बाधा डाली थी। इस पर सिंधिया भी उठे और बोले, जिसका बनर्जी ने सिंधिया पर निशाना साधा और कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें स्वीकार ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। बाद में हुए होहल्ले के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। बुधवार को ही शाम को सदन की बैठक फिर से हुई तो बनर्जी ने माफी मांगी पर सिंधिया ने माफी स्वीकार करने से मना कर दिया था।

## आदर्श क्रेडिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर चुकी है। ई.डी. मामले में एस.ओ.जी. की ओर से दर्ज धोखाधड़ी से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।

## प्रदेश की बार एसोसिएशनों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जगह-जगह सी.सी.टी.वी. कैमरे और स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अलावा, मतदान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा।

महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष पद पर पांच प्रत्याशियों- राजेश महर्षि, महेन्द्र शांडिल्य, संगीता शर्मा, इन्द्रेश शर्मा व राजीव सोगरवाल के बीच मुकाबला है,

# 'भारत में प्रदूषण से 2009-2019...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल के शोधकर्ता भी शामिल हैं, ने पाया कि भारत की 1.4 बिलियन आबादी पी.एम. 2.5 के स्तर के संपर्क में बनी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा अनुशासित वार्षिक औसत प्रति क्यूबिक मीटर वार्षिक औसत से अधिक है।

टीम ने यह भी पाया कि भारत की लगभग 82 प्रतिशत आबादी, या 1.1 बिलियन लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां का पी.एम. 2.5 स्तर का वार्षिक औसत इंडियन नेशनल एम्बिएंट द्वारा अनुशासित 40 माक्रॉन्स प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है।

दिल्ली और एन. सी. आर. को विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में, "दिल्ली की 21-सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना" नामक

जबकि महासचिव पद पर सात प्रत्याशी रमित पारीक, अशोक कुमार यादव, अंकित सेठी, निशांत शर्मा, दीपेश शर्मा, डॉ. रामरूप मीना व शिवराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अन्य पदों के लिए भी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहेगा। इसी तरह दी बार एसोसिएशन, जयपुर में भी सुबह आठ से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी राम मनोहर शर्मा ने बताया

कि अध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशी -संदीप लुहाडिया, सोमेश चन्द्र शर्मा, राजेश चौधरी, सुरेन्द्र सिंह राजावत, राजनीश गौड़ व प्रमोद कुमार शर्मा चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह महासचिव पद पर 9 प्रत्याशी- मनीष गगरानी माहेश्वरी, अर्जुन राजपुरोहित, पुष्पेन्द्र कुमार भारद्वाज, बिन्दिया शर्मा, गोविन्द सिंह चूडावत, पंकज शर्मा पचलंगिया, कुलभूषण गौड़, जयराम सिंह व उमेश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं।

कार्यक्रम के तहत नए कदम उठाए गए। ड्रोन के माध्यम से, सघन आबादी वाले उन क्षेत्रों में सघन प्रदूषण वाले परिया पर फुहारों की बौछार करने संबंधी पायलट प्रदूषण प्रोजेक्ट भी है, जहां दूक जैसे पारंपरिक यातायात के साधनों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जहां, ड्रोन के उपयोग की वकालत करते आए हैं, वहीं, मूल्यांकन में शामिल अधिकारी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि ड्रोन टैकनोलॉजी बहुत अधिक महंगी है तथा वर्तमान तरीकों के मुकाबले

इनसे कोई खास प्रगति नहीं होती है। इस बीच, लैसैट अध्ययन में पाया गया कि सर्वे वाले पीरियड में पी.एम.2.5 पोल्यूशन 10 माइक्रॉन्स प्रति क्यूबिक मीटर की दर से बढ़ा। इसका संबंध, प्रति वर्ष 8.6 प्रतिशत ऊंची मृत्यु दर से पाया गया। अध्ययन में, 2009 से 2019 की अवधि में प्रति वर्ष हुई मौतों पर फोकस किया गया, जिसका डेटा सिविल रैजिस्ट्रेशन सिस्टम से लिया गया। पी.एम. 2.5 सघनता का डेटा सैटलाइट तथा तकरीबन एक हजार ग्राउण्ड मॉनिटरिंग स्टेशन से लिया गया। यह भी पाया गया कि सभी सालों में पी.एम. 2.5 का विस्तृत एक्सपोजर था। इसका न्यूनतम स्तर अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में तथा उच्चतम स्तर गाजियाबाद व दिल्ली में पाया गया।

अशोक युनिवर्सिटी और नई दिल्ली के सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल के शोधकर्ताओं ने शोध में यह भी पाया कि भारत की 1.4 अरब आबादी लगातार पी.एम. 2.5 स्तर के वायु प्रदूषण के सम्पर्क में रहती है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा अनुशासित 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है, वहीं, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में सबसे कम है। दिल्ली एन.सी.आर. और गाजियाबाद विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र हैं।

अशोक युनिवर्सिटी और नई दिल्ली के सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल के शोधकर्ताओं ने शोध में यह भी पाया कि भारत की 1.4 अरब आबादी लगातार पी.एम. 2.5 स्तर के वायु प्रदूषण के सम्पर्क में रहती है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा अनुशासित 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है, वहीं, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में सबसे कम है। दिल्ली एन.सी.आर. और गाजियाबाद विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र हैं।

## जमवारामगढ़ बार चुनाव परिणाम पर रोक

जयपुर, 12 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन, जमवारामगढ़ के शुक्रवार को होने वाले चुनाव का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने वर्तमान कार्यकारिणी को पद पर बने रहने को कहा है। वहीं, अदालत ने मामले में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव और दी बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ की चुनाव समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गौयल की एकलपीठ ने यह आदेश दी बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अनुराग पारीक और प्रियंका पारीक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बार एसोसिएशन के संविधान की धारा 12 के अनुसार, एसोसिएशन के चुनाव दो साल में होते हैं। बार कौंसिल ऑफ

बार एसोसिएशन जमवारामगढ़ के अध्यक्ष की याचिका पर चुनाव समिति को नोटिस जारी।

राजस्थान के पूर्व में जारी पत्र के अनुसार भी याचिकाकर्ता एसोसिएशन का कार्यकाल दो साल का ही है। संविधान की पालना करते हुए एसोसिएशन की ओर से गत चुनाव दिसंबर, 2023 में कराए गए थे। ऐसे में आगामी चुनाव दिसंबर, 2025 में होने हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि कुछ वकीलों ने संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए 13 दिसंबर, 2024 को ही चुनाव कराना तय कर चुनाव संचालन समिति का भी गठन कर लिया। संचालन समिति शुक्रवार को चुनाव कराने जा रही है, जबकि यह एसोसिएशन के प्रावधानों के खिलाफ है। ऐसे में चुनाव संचालन समिति को कार्रवाई को रद्द किया जाए।

## केजरीवाल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) यही समय है कि ए. आई. सी. सी. उनकी नियुक्ति को तार्किक आधार पर देखे और समझे की दोहरी जिम्मेवारी से पार्टी को लाभ नहीं होगा।

# देवेगौड़ा ने अपने पोते निखिल को उत्तराधिकारी घोषित किया

## निखिल केन्द्रीय मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी के पुत्र हैं

- लक्ष्मण बैकट कुची -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -  
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी जनता दल (सैकुलर) ने वंशवादी उत्तराधिकारी की योजना बनाली है और पार्टी के प्रमुख तथा पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते व केन्द्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के पुत्र निखिल कुमारस्वामी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा।

लेकिन पार्टी में इस योजना का विरोध हो रहा है। कई नेता निखिल के खराब चुनावी रिकॉर्ड का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने तीन चुनाव लड़े और तीनों हार गए। वर्तमान में, वे जद (एस) की कर्नाटक युवा शाखा के अध्यक्ष हैं और उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। इस समय केन्द्रीय मंत्री कुमारस्वामी पार्टी अध्यक्ष हैं और मंत्री के रूप में उनकी व्यस्तता को देखते हुए उनके पुत्र को पार्टी अध्यक्ष बनाने का विचार चल रहा है। जैसे तमिलनाडु में द्रमुक, और आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी, तेलंगाना में बी. आर. एस. परिवार को पार्टियां हैं, उसी तरह जद (एस) भी पारिवारिक पार्टी है, उस पर देवेगौड़ा परिवार का पूर्ण नियंत्रण है।

इस योजना का खुलासा खुद

एच.डी. देवेगौड़ा की इस घोषणा से पार्टी में नाराजगी है, क्योंकि निखिल आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते हैं।

दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों की प्रमुख पार्टियां एक परिवार विशेष की विरासत बन गई हैं। तमिलनाडु में द्रमुक, आंध्र में तेलुगुदेशम और तेलंगाना में बी.आर.एस. सिर्फ परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा रही हैं।

देवेगौड़ा ने किया है। लेकिन पार्टी के लोग निखिल को लेकर चिंतित हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मांड्या सीट से निर्दलीय प्रत्याशी एस. अम्बरीश से हार गए थे और 2023 में रामनगर सीट से कांग्रेस के एन. ए. इकबाल हुसैन

से हार गए थे और हाल ही में उन्हें चन्नयना सीट से कांग्रेस के सी. पी. योगेश्वर ने 25,000 वोटों से हराया।

जद (एस) की कोरे कमेटी के चेयरमैन और चामुंडेश्वरी के विधायक जी. टी. देवेगौड़ा जैसे चन्द ही नेता हैं, जिन्हें नेतृत्व के लिए पार्टी का समर्थन प्राप्त है। पूर्व विधायक एस. आर. महेश का नाम भी चर्चा में था। ऐसी धारणा थी कि वंशवादी पार्टी होने के तर्कों से पार्टी की छवि व चुनावी संभावनाएं प्रभावित हो रही है।

जब से देवेगौड़ा ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह संकेत दिया है कि निखिल को जद (एस) अध्यक्ष बनाया जाएगा, तब से पार्टी में असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम पार्टी की जिम्मेदारी निखिल को देंगे। उसके पास पारिवारिक पृष्ठभूमि है और राजनीति का अनुभव है।

यह तो तय है कि देर-समेर यह बदलाव होगा। लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी निरन्तर कमजोर हो रही है, खासकर भाजपा से गठबंधन के बाद। भाजपा तेजी से दक्षिण भारत में अपने पैर फैला रही है। कर्नाटक में जद (एस) की कीमत पर और तमिलनाडु में अनाद्रमुक की कीमत पर।

## किसी भी तरह के सर्वे, धार्मिक स्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिनियम के तहत, विचार/सुनवाई नहीं हो सकती। मौजूदा कार्यवाहियों उन याचिकाओं से उत्पन्न हुई हैं, जिनमें इस अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इनमें भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका भी शामिल है। उपाध्याय की याचिका में दलील दी गई है कि हमलों के दौरान कथित रूप से छीन लिये गये धार्मिक स्थलों के लिये कानूनी समाधान प्राप्त करने से दुखी हिन्दुओं, जैनों, बौद्धों तथा सिक्कों को रोककर, यह एक ऐतिहासिक अन्यायों को स्थायी बना रहा है।

जमीयते-उलेमा-ए हिन्द, जिसने 2022 में इन कार्यवाहियों में शामिल होने की माँग की थी, ने कहा है कि ये याचिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से इस्लामिक धार्मिक स्थलों को

निशाना बना रही हैं। अन्य याचिकाएं, जिसमें विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की याचिका भी शामिल है, अन्य कई याचिकाओं के साथ, इसी मामले में दायर की गई हैं।

इस केस का नतीजा विभिन्न विवादित स्थलों से सम्बन्धित विवादों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें शामिल हैं- वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही इंदगाह मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद तथा राजस्थान में अजमेर की दरगाह। इन धार्मिक स्थलों एवं सम्पत्तियों पर हिन्दुओं ने अपना अधिकार मांगा है तथा कहा है कि ये धार्मिक स्थल मन्दिरों पर बनाये गये हैं।

मुस्लिम पक्षों ने इन मुकदमों का विरोध किया है तथा पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुये, इन मुकदमों को जारी रखे जाने को चुनौती ही है।



## महिला सम्मेलन

# राज्यस्तरीय समारोह

14 दिसम्बर, 2024 | अपराह्न 12:00 बजे

स्थान: उदयपुर

मुख्य अतिथि  
श्री भजनलाल शर्मा  
माननीय मुख्यमंत्री

सुश्री दिया कुमारी  
माननीया उप-मुख्यमंत्री

विशिष्ट अतिथि  
डॉ. मंजू बाघमार  
माननीया महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

श्री हेमंत मीणा  
माननीय राज्यस्त्री मंत्री

निभाई जिम्मेदारी - हर घर खुशहाली

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान